(a) what is the criteria for finalising agenda for NDC meeting and to what extent the State Governments and NGO's are involved in fixing agenda;

(b) the criteria for monitoring the decision taken at NDC meetings and the extent to NGO involvement thereof;

(c) what were the salient outcome of recently concluded NDC meet; and

(d) whether the council has fixed any time-bound programme for alleviation of rural poverty?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI RAM NAIK): (a) The agenda for a meeting of National Development Council (NDC) can cover any subject falling within the purview of the *functions of the Council, as contained in the* Resolution dated 7th October, 1967 on the subject.

2. The functions of the NDC are:

(i) to prescribe guidelines for the formulation of the National Plan, including the assessment of resources for the Plan;

(ii) to consider the National Plan, as formulated by the Planning Commission;

(iii) to consider the important questions of social and economic policy affecting *national development.*

(iv) to review the working of the Plan from time to time and to recommend such measures as are necessary for achieving the aims and targets set out in the national Plan, including measures to secure the active participation and cooperation of the people, improve the efficiency of the administrative services, ensure the fullest development of the less advanced regions and sections of the community and, through sacrifice borne equally by all citizens, build up resources for national development.

(b) and (c) Decisions taken at the meetings of the NDC are monitored by the Planning Commission. The following decisions were reached at the meeting of the NDC held on 19th February, 1999:—

(1) The NDC approved the Ninth Five Year Plan (1997—2002), as placed before the Council.

(2) The NDC endorsed the recommendations of the NDC Committee on Power and urged the Union, State and UT Governments to implement these recommendations on priority.

(3) It was suggested by the NDC that, while revising the administered prices of essential commodities, a balance needs to be struck between the interests of farmers and consumers, particularly the poorer sections of society, and the macro-economic imperatives of fiscal stabilisation and control of inflation.

(4) The NDC decided to constitute two Sub-Committees under the Chairmanship of Deputy Chairman, Planning Commission, with members from the Central Ministries and States, to go into (a) the criteria for allocation of funds under major rural poverty alleviation schemes and (b) the transfer of Centrally Sponsored Schemes (CSS) and the modalities involved therein.

(d) While the Ninth Plan envisages continuation of various ongoing poverty alleviation schemes, no time-bound programme for the same has been determined.

देश की अर्थव्यवस्था के संबंध में आकलन

2616. श्री परमेश्वर कुमार अग्रवाला: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन ने अर्थवयवस्था के आकलन संबंधी प्रक्रिया में व्यापक परिवर्तन किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप अर्थव्यव्था संबंधी सांख्यिकीय आंकड़ों, सकल घरेलू उत्पाद, उद्योग, कृषि और अन्य प्रमुख क्षेत्रों की वृद्धि दर में क्या परिवर्तन हुए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) और (ख) सांख्यिकी विभाग में केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (के.सां.सं.) ने पूर्ववर्ती श्रृंखला आधार वर्ष 1980-81 के स्थान पर आधार वर्ष 1993-94 पर आधारित राष्ट्रीय लेखा की नई श्रृंखला फरवरी 1999 में आरंभ की है। नई श्रृखला में आधार वर्ष में परिवर्तन के अतिरिक्त (स्थिर मूल्य अनुमानों हेतु) कवरेज तथा और अधिक अद्यतन आंकड़ों के प्रयोग के संदर्भ में सुधार किए गए हैं। नई श्रृंखला में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा आयोजित रोजगार तथा बेरोजगारी सर्वेक्षण संगठन द्वारा आयोजित रोजगार तथा बेरोजगारी सर्वेक्षण 1993-94 के परिणामों पर आधारित कार्यबल अनुमानों को गिनती में लिया जाता है, जिसमें लोगों की गतिविधियों को, विशेषकर महिलाओं के बारे में, जनसंख्या जनगणना के मुकाबले में अधिक बेहतर ढंग से लिया गया है। राष्ट्रीय लेखे की कवरेज को कुछ आर्थिक गतिविधियों को और अधिक औचित्यपूर्ण ढंग से सम्मिलित करते हुए तथा कुछ उत्पादों जैसे आंगन/प्रांगण उत्पादन, पुष्पोत्पादन, कुछ बागवानी फसलें, गहरे समुद्र में पछली पकड़ना, झींगा, निजी कोयला खानें तथा प्रक्षालन, इंजनों तथा अन्य रेल उपस्करों की संपूर्ण मरम्मत, कर्मचारी भविष्य निधि संगठनों की सेवाएं, दूरदर्शन तथा रेडियो प्रसारण से संबंधित निजी संचार सेवाएं, साफ्टवेयर परामर्शी सेवाएं, सिलाई गतिविधियां तथा अर्द्धसरकारी निकायों का अलग से मूल्यांकन करते हुए सुधारा गया है।

(ग) सकल घरेलू (देशीय) उत्पाद के प्रचलित मूल्यों पर व्यापक क्षेत्रीय अनुमान तथा नई श्रृंखला (आधार 1993-94) तथा पुरानी श्रृंखला (आधार 1980-81) में स्थिर मूल्यों पर इन क्षेत्रों की वृद्धि दरें संलग्न विवरण 1 और 2 में दी गई हैं।

विवरण-1

राष्ट्रीय लेखे की नई और पुरानी श्रृंखलाओं में स्थिर मूल्यों पर अर्थव्यवस्था के व्यापक क्षेत्रों में सकल घरेलू उत्पाद के अनुमान

(रु. करोड़ में)

वर्ष		कृषि	उद्योग	सेवाएं	कुल
1993-94	नई श्रृंखला	242438	205800	350839	799077
	पुरानी श्रृंखला	223705	204042	305127	732874
	अंतर %	8.4	0.9	15.0	9.0
1994-95	नई श्रृंखला	284042	247542	411824	943408
	पुरानी श्रृंखला	259064	250232	358723	868019
	अंतर %	9.6	-.1	14.8	8.7
1995-96	नई श्रृंखला	312791	299792	490655	1103238
	पुरानी श्रृंखला	276852	305339	424095	1006286
	अंतर %	13.0	-1.8	15.7	9.6
1996-97	नई श्रृंखला	376091	335269	573899	1285259
	पुरानी श्रृंखला	310144	344592	494479	1149215
	अंतर %	21.3	-2.7	16.1	11.8

विवरण-2

राष्ट्रीय लेखे की नई और पुरानी श्रृंखलाओं में स्थिर मूल्यों पर अर्थव्यवस्था के व्यापक क्षेत्रों में वृद्धि की दर

वर्ष	कृषि		उद्योग		सेवाएं		कुल	
	नई श्रृंखला	पुरानी श्रृंखला	नई श्रृंखला	पुरानी श्रृंखला	नई श्रृंखला	पुरानी श्रृंखला	नई श्रृंखला	पुरानी श्रृंखला
1994-95	5.4	5.1	9.3	10.4	8.5	7.7	7.8	7.8
1995-96	0.2	-3.0	12.2	12.5	9.8	10.4	7.6	7.2
1996-97	9.4	7.9	6.0	6.4	8.0	8.1	7.8	7.5
1997-98	-1.0	-1.5	5.9	5.5	8.2	8.8	5.0	5.1